



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खंड I

PART I—Section 1

प्राविकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १६८] नई विल्सो, मंगलवार, अक्टूबर ३१, १९६७/कार्तिक, ९, १८८९
 No. १६८] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER ३१, १९६७/KARTIKA ९, १८८९

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
 as a separate compilation.

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

संस्कार

नई विल्सो, ८ सितम्बर १९६७

संख्या २२—पी० एल० ए० ५९/६७.—श्रम और रोजगार मंत्रालय आज्ञा संख्या २८(९२)/६४ एल० आर० ४ दिनांक १९ मार्च, १९६६ द्वारा भारत सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) के खंड (ब) के अधीन एकमात्र सदस्य के रूप में श्री सलीम एम० मच्चेट से जांच न्यायालय गठित की है और उन्हें निम्न अनुसूची में उल्लिखित मामला सौंपा है :—

प्रनुसूची

“कलकत्ता पत्तन तथा अन्य बड़े पत्तनों में ‘बी’ श्रेणी के मजदूरों की नौकरी की शर्तों के बारे में जांच करना और २१ जुलाई, १९५८ को भारत के असाधारण राजपत्र भाग १ खंड १ में प्रकाशित

पत्तन और गोदी मजदूरों की मांगों पर जांच करने के लिये नियुक्त विशेषाधिकारी की रिपोर्ट पर परिवहन और संचार मंत्र नय (परिवहन विभाग) में भारत सरकार के संख्या 23-पी०एल०ए० (87)/58 दिनांक 20 जुलाई, 1958 के प्रस्ताव के साथ सरकार को सिफारिश करना कि किस तरह अंग्रेजी सीमा तक उपरोक्त 'बी' श्रेणी के मजदूरों की नौकरी की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये।"

पत्र संख्या 28(92)/64 एल०आर० 4 दिनांक 15 अप्रैल, 1966 द्वारा अम तथा रोजगार मंत्रालय ने न्यायालय द्वारा पूछे एक प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया था कि जांच का सम्बन्ध कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, विशाखापत्तनम् और कोलकाता के पांच बड़े पत्तनों में 'बी' श्रेणी के मजदूरों की सेवाओं की शर्तों से होना चाहिये।

3. बाद से भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 28(92)/64 एल०आर० 4, दिनांक 4 नवम्बर, 1966 द्वारा श्री सर्वजीव एम०मर्जेंट को जांच न्यायालय के एक मात्र सदस्य के रूप में निम्न अनुसूची में उल्लिखित मामले को भी सौंपा :—

अनुसूची

"बड़े पत्तनों की 'सी' श्रेणी के मजदूरों की सेवाओं की शर्तों, की जांच करना और भारत के साथ राजपत्र में 21 जुलाई 1958 को प्रकाशित पत्तन और गोदी कर्मचारियों की मांगों में जांच करने के लिये नियुक्त विशेषाधिकारी की रिपोर्ट पर परिवहन तथा संचार मंत्रालय में भारत सरकार (परिवहन विभाग) संख्या 23-पी०एल०ए० (87)/58 दिनांक 20 जुलाई, 1958 के संस्ताव के साथ सरकार को सिफारिश करना कि किस तरह और किस सीमा तक उपरोक्त 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये।"

4. भारत सरकार को जांच न्यायालय की रिपोर्ट मिल गई है। यह रिपोर्ट भारत के अन्तर्भारत राजपत्र भाग 2 अनुभाग 3 (2) विनांक 19 अगस्त, 1967 में एस०ओ० 2867 के अन्तर्गत पृष्ठ 1365 से 1423 तक में प्रकाशित हुई है।

5. भारत सरकार ने निश्चय कि यह कि जांच न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार कर दिया जाना चाहिये। इस निश्चय के परिणामस्वरूप भारत में बड़े पत्तनों के 'बी' और 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों को निम्न अतिरिक्त रियायतें दी जायेंगी :—

(1) 'बी' श्रेणी कर्मचारियों के लिये उपस्थिति धन :

'बी' श्रेणी के वे कर्मचारी जो काम पर स्थिर करते हैं परन्तु जिन्हें काम नहीं दिया जाता उन्हें 1 अक्टूबर 1967 से प्रति बुलाई 1.75 रु का उपस्थिति धन दिया जायेगा। इस उपस्थिति भत्ते की राशि पर अलग से कोई मंहगाई भत्ता नहीं दिया जायेगा।

(2) विशेषाधिकार छट्टी :

'बी' श्रेणी के कर्मचारियों को प्रति भात दिनों की हाजिरी पर एक दिन की दर से विशेषाधिकार छट्टी दी जायेगी जो 1 जनवरी 1967 से गिनी जायेगी। छट्टी की यह दर उन सभी कर्मचारियों पर लाग रहेगी जिन्हें 'बी' श्रेणी में एक वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है। यह विशेषाधिकार छट्टी सीन वर्षों तक जीतनी छट्टी होगी उस सीमा तक जमा की जा सकेगी।

(3) बीमारी की छुट्टी :

एक वर्ष में 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों को आधे बेतन पर चौदह दिनों की बीमारी की छुट्टी या पूरे बेतन पर सात दिनों की बीमारी की छुट्टी दी जायेगी जो 1 जनवरी 1967 से गिनी जायेगी। महल्ली आधे बेतन पर चौगामी दिन, तक या पूर्ण बेतन पर ब्राह्मी दिनों तक जमा की जा सकेगी।

(4) आकस्मिक छुट्टी :

1 जनवरी, 1968 में 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों को एक वर्ष में पांच दिनों की आकस्मिक छुट्टी दी जायेगी। यह छुट्टी अधिकार के रूप में नहीं ली जायेगी किन्तु आवश्यक और अदृष्ट पर्याप्तियों में ली जा सकेगी। आकस्मिक छुट्टी जमा नहीं की जा सकेगी।

(5) सवेतन छुट्टियां (हालीडे) :

एक वर्ष में 'बी' और 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों को पांच सवेतन छुट्टियां दी जायेगी। यह छुट्टी अधिकार के रूप में नहीं ली जायेगी किन्तु आवश्यक और अदृष्ट पर्याप्तियों में ली जा सकेगी। आकस्मिक छुट्टी जमा नहीं की जा सकेगी।

(6) प्रेचुटी :

1 अक्टूबर, 1967 में 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों पर बम्बई पोर्ट टर्मिनल बेनिफिट (अस्थायी मेवा) नियम के अन्तर्गत अपने अस्थायी कर्मचारियों के लिये बम्बई पोर्ट टर्मिनल स्कीम की लाइन पर ग्रेचुटी की एक स्कीम लागू की जायेगी।

अधिकार प्राप्त करने वाले या सेवात प्रेचुटी का अधिकारी होने की दशा से पूर्व 'बी' श्रेणी के कर्मचारी के 'ए' श्रेणी में पदोन्नत होने पर कर्मचारी को 'ए' श्रेणी में पेशन तथा अवकाश प्राप्त प्रेचुटी के अन्तर्गत उसे लाभ दिये जाने के प्रयोजन के लिये उभयनी 'बी' श्रेणी की सेवाओं का समय भी गिना जायेगा।

नटीय कर्मचारियों के मास्टन में जो पहले 'बी' श्रेणी में पदोन्नत किये जा चुके हैं या जिन्हें अब 'सी' से 'बी' श्रेणी में पदोन्नत किया जाय, 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों की चार लगातार वर्षों से अधिक की पिछली मेवायें, इस स्कीम के अन्तर्गत प्रेचुटी के लाभों के प्रयोजन के लिये वैसी ही गिनी जायेगी मानों वे 'बी' श्रेणी की सेवायें थीं।

(7) विकिस्ता सुविधा और मकान :

समस्त बड़े पन्नों में 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों को 'ए' श्रेणी के समान सुविधाये मिलेगी परन्तु चिकित्सा भवायता और मकान के लाभ के सम्बन्ध में 'ए' श्रेणी का दावा पहले होगा।

(8) 'ए' श्रेणी में पदोन्नति :

इसके बाद बम्बई, मद्रास, कोलकाता और विशाखापत्तनम् पन्नों में स्वाभाविक धरति या अन्य कारणों की वजह से 'ए' श्रेणी में होने वाले सब रिक्त स्थान, 'बी' रजिस्टर में सर्वोच्च कर्मचारी के पदोन्नत द्वारा भरे जायेगे। कलकत्ता पत्तन में 1 अक्टूबर, 1967 से उच्चता के अन्याय मौजूदा 'बी' श्रेणी के 520 कर्मचारी 'ए' श्रेणी में पदोन्नत किये जायेंगे किन्तु पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर दोनों स्थानों अर्थात् विभिन्न जेटियों और गोदियों में भी कार्य करना होगा। कलकत्ता में 'ए' श्रेणी में पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारियों में मे बनाये जाने वाले दलों के गठन का काम कलकत्ता पोर्ट कमिशनर के लिये लोड हिया गया है।

(9) विशाखापत्तनम् पत्तन में ए 1 श्रेणी की समाप्ति :

विशाखापत्तनम् पत्तन में ए 1 श्रेणी का पदनाम समाप्त कर दिया जायेगा और ए 1 श्रेणी के कर्मचारी जिस दिन से उस श्रेणी में रखे गये हैं उस समय से 'ए' श्रेणी के स्थायी कर्मचारी माने जायेंगे और 'ए' श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाले समस्त लाभ उन्हें दिये जायेंगे ।

(10) कलकत्ता पत्तन में 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मकान किराया [भत्ता :

1 अक्टूबर, 1965 से कलकत्ता पत्तन के 'बी' श्रेणी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता बढ़ा कर 15 रुपये प्रति माह कर दिया जायेगा ।

(11) कलकत्ता पत्तन में 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों के लिये बर्बी (यूनीफार्म) :

कलकत्ता पत्तन के 'बी' श्रेणी के तटीय कर्मचारियों को तीन बर्बी में एक बार एक ऊनी जर्मी दी जायेगी । पहली सप्लाई नवम्बर, 1967 में की जायेगी ।

(12) रोस्टर छुट्टी (आफ) :

जब 'बी' श्रेणी के कर्मचारी को जब कि मान्यताएँ पर इस श्रेणी के कर्मचारियों का बुकिंग बन्द होता है, किसी दिन छुट्टी दी जाती है और वह आराम के दिन के तुरन्त पहले 7 दिनों की अवधि के बीच में पड़ती है तब उस दिन की अनुपस्थिति मजदूरी नहिं गेस्टर छुट्टी (आफ) के हक्क के प्रयोजन के लिये विकल्पक नहीं मानी जायेगी ।

(13) 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में सिकारियों :

(1) 'सी' श्रेणी में चार वर्षों की निरन्तर सेवाओं की पूर्ति पर, 'सी' श्रेणी के कर्मचारी स्वतः 'बी' श्रेणी में पदोन्नत हो जायेगे और 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों की मेज़ा लाभों को प्राप्त करने लगें । यह नियम कलकत्ता पत्तन पर लागू नहीं होगा ।

(2) कलकत्ता पत्तन के सिवाय, 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या, 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों की पूर्ण संख्या की 15 प्रतिशत तक सीमित रहेगी ।

यदि सब योग्य 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों को 'बी' श्रेणी में पदोन्नत करने के बाद 'सी' श्रेणी में बचे कर्मचारियों की संख्या, 'ए' 'बी' श्रेणियों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक है तो यह बहोतरी 'सी' श्रेणी में उस समय तक कायम रखी जाएंगी जब तक मान्यता 'सी' श्रेणी की संख्या अपेक्षित स्तर तक नहीं आ जानी है ।

(3) चार वर्षों के बाद 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा दशाओं, बेनन और रोजगार के प्रश्न का पुनर्विलोकन किया जायेगा ।

(4) जहां कही कर्मचारियों के लिये उपरोक्त वर्णन सेवा दशाओं में मौजूदा सेवा दशायें अधिक अच्छी और उपयुक्त हैं वहां मौजूदा सेवा दशायें लागू की जायेंगी ।

(5) भारत सरकार श्री मलीम ग़ामू मर्चेंट को मौपी हुई जाच के सम्बन्ध में उनके द्वारा किये गये कार्य की मरहना करती है ।

आवेदन

आवेदन दिया जाता है कि इस संस्थाव की एक प्रतिलिपि संबद्ध हितों को प्रेषित कर दी जाये और इसे सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

१०. कोशेट,
भारत सरकार के संयुक्त सचिव ।